



'भारत और इजराइल आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे', यरूशलम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर

यरूशलम/नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हनुक्का पर्व के दौरान हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल दोनों आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करते और इसके सभी स्वरूपों के खिलाफ लड़ाई में निरंतर सहयोग जारी रहेगा। हमले में 15 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हुए थे।

जयशंकर इजराइल की दो दिवसीय यात्रा पर तेल अवीव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने इजराइली समकक्ष गिदोन मोशे सार के

साथ द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और गाजा शांति योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत-इजराइल साझेदारी पिछले दशक में मजबूत हुई है और इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

जयशंकर ने एस फोरम में भी भाग लिया और अबू धाबी से तेल अवीव आए। उनकी यात्रा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आगामी भारत यात्रा की तैयारियों के बीच हो रही है, जिससे दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संवाद को बढ़ावा मिलेगा।

Breaking News | विदेशी धरती पर पीएम मोदी का जलवा कायम

विदेशी धरती पर पीएम मोदी का जलवा कायम, अब इस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशां' से नवाजा

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से विदेशी धरती पर सर्वोच्च सम्मान मिला है। आज अदीस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में, इथियोपिया के प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. अबी अहमद ने भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किया।

इस सम्मान को पाने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा?

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक से यह



पुरस्कार ग्रहण करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने इसे अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री डॉ. अबी और इथियोपिया की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. अबी के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उनकी पहलों की सराहना की। राष्ट्र निर्माण में ज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय शिक्षकों के लिए एक सदी से

अधिक समय से इथियोपिया की प्रगति और विकास में योगदान देना सौभाग्य की बात रही है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों और इथियोपियाई लोगों को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह पुरस्कार उन सभी भारतीयों और इथियोपियाई लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से इस सम्मान से नवाजे जाने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया। यह पुरस्कार भारत और इथियोपिया के बीच घनिष्ठ साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और वैश्विक दक्षिण के सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी सहायक है। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण यहां देखा जा सकता है।

IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने मिनी-ऑक्शन में जेसन होल्डर और टॉम बैटन को किया शामिल



आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम को संतुलित और मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। कप्तान शुभमन गिल, स्टार स्पिनर राशिद खान, सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन, तेज गेंदबाज सिराज और रबाडा को पहले ही रिटेन किया गया था। ऑक्शन में सबसे बड़ी खरीद जेसन होल्डर (7 करोड़) रही, जबकि टॉम बैटन 2 करोड़ में शामिल हुए। भारतीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा (90 लाख) और पृथ्वीराज यर्रा (30 लाख), साथ ही इंग्लिश तेज गेंदबाज ल्यूक वुड (75 लाख) टीम में शामिल हुए। ये खरीद टीम को मध्य क्रम, बैकअप तेज गेंदबाजी और पावर हिटिंग में मजबूती देगी।

हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में होंगी समर्पित एनआईए अदालतें, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली | आतंकवाद से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने देश के हर राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी उच्चतम न्यायालय को दी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत 10 से अधिक मामले लंबित हैं, वहां एक से अधिक विशेष एनआईए अदालतें गठित की जाएंगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष एनआईए सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव की सभी राज्यों के गृह सचिवों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में एनआईए मामलों के लिए



अतिरिक्त न्यायिक पद, बुनियादी ढांचा और आवश्यक वित्तीय प्रावधान पर सहमति बनी है। केंद्र ने अतिरिक्त एनआईए अदालतों की स्थापना के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के रूप में एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा है। वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से पेश एसडी संजय ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में संगठित अपराध और आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के

लिए 16 विशेष अदालतें स्थापित की जा रही हैं, जो तीन महीने के भीतर कार्य करना शुरू कर देंगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने एनसीआर में क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों पर चिंता जताते हुए पूरे क्षेत्र में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कड़े कानून को लागू करने की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा कि

राज्य सीमाओं का फायदा उठाकर जांच और सुनवाई में देरी कराते हैं। पीठ ने गैंगस्टर महेश खत्री और नक्सल समर्थक कैलाश रामचंदानी के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी का लाभ अपराधियों को मिल जाता है, जो समाज और राष्ट्रहित में नहीं है। न्यायमूर्ति बागची ने ऐसे मामलों में एनआईए अधिनियम लागू करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कार्यवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2026 में तय की है। इससे पहले, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा अदालतों को विशेष अदालत घोषित करने पर नाराजगी जताते हुए नई अदालतों के गठन के निर्देश दिए थे।

3 सालों में 438 CAPF कर्मियों ने की आत्महत्या, 7 की हत्या, सरकार ने जारी किए आंकड़े

3 सालों में 438 CAPF कर्मियों ने की आत्महत्या



नई दिल्ली: सरकार ने लोकसभा को बताया कि पिछले तीन वर्षों (2023-2025) में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), असम राइफल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के 438 कर्मियों ने आत्महत्या की, जबकि सात सहकर्मियों की हत्या की गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी लिखित उत्तर में दी।

आत्महत्या की सबसे अधिक घटनाएं सीआरपीएफ में 159, बीएसएफ में 120 और सीआईएसएफ में 60 दर्ज की गईं। 2023 में आत्महत्या के

मामले 157 थे, जो 2025 में घटकर 133 हो गए। सहकर्मी हत्या की घटनाएं 2023 में 2, 2024 में 1 और 2025 में 4 दर्ज हुईं।

मंत्री ने बताया कि 2014-2025 के बीच सीपीएफ और असम राइफल के 23,360 कर्मियों ने इस्तीफा दिया, जबकि बीएसएफ में 7,493, सीआरपीएफ में 7,456 और सीआईएसएफ में 4,137 इस्तीफे दर्ज किए गए। 2025 में अब तक 3,077 इस्तीफे हुए हैं।

सीपीएफ कर्मियों की झूटी आमतौर पर 8 घंटे की शिफ्ट में होती है, लेकिन परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार यह बदल सकती है। बटालियन संरचनाओं में आराम, छुट्टी और प्रशिक्षण के प्रावधान शामिल हैं।

'महात्मा गांधी मेरे परिवार जैसे हैं, लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान भड़कीं प्रियंका गांधी

नई दिल्ली | लोकसभा में मंगलवार को 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्ढा ने सरकार पर रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान महात्मा गांधी को लेकर सत्ता पक्ष के एक सांसद की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी तीखी प्रतिक्रिया देती नजर आईं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि इस विधेयक में महात्मा गांधी का नाम शामिल न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी दौरान सत्तापक्ष के एक सदस्य ने टिप्पणी की कि "महात्मा गांधी आपके परिवार के नहीं थे"। इस पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, "हां, महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे,



लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं। यही भावना पूरे देश की है।" उनके इस बयान के बाद सदन में कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही।

विधेयक के आर्थिक प्रभावों पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में पहले केंद्र सरकार 90 प्रतिशत तक अनुदान देती थी, जबकि नए विधेयक के तहत अधिकांश राज्यों को केवल 60 प्रतिशत

अनुदान मिलेगा। इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, खासकर उन राज्यों पर जो पहले से ही केंद्र से लंबित जीएसटी बकाया का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सरकार की प्रवृत्ति समझ से परे है। नाम परिवर्तन के चलते केंद्र को अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण बढ़ा रही है और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। अपने भाषण के अंत में कांग्रेस महासचिव ने विधेयक को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर नया विधेयक लाया जाए और इसे गहन अध्ययन तथा व्यापक चर्चा के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए।

वहीं संसद परिसर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूछे गए सवालों पर प्रियंका गांधी ने दोहराया कि इस मामले में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जबर्न इस केस को घसीट रही है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होगी और सच्चाई सबके सामने आएगी।

SAR: बंगाल टॉप पर, पांच राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सबसे अधिक नाम काटे गए

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत मृत, स्थायी रूप से शिफ्ट हुए और डुप्लिकेट वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 58 लाख 20 हजार 899 मतदाताओं के नाम काटे गए। इनमें 24 लाख 16 हजार मृत मतदाता, 32 लाख 65 हजार बाहर स्थानांतरित और 1 लाख 38 हजार से अधिक डुप्लिकेट मतदाता शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि अब अगले साल 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। जिनके नाम गलती से कट गए हैं, उनके नाम 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में वापस जोड़े जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ही 85 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम 2002 की



एसआईआर लिस्ट से मेल नहीं खा पाए। ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजकर जानकारी ली जाएगी। अन्य राज्यों में भी नाम काटे गए हैं। राजस्थान में 41 लाख 84 हजार 819, पुडुचेरी में 1 लाख

3 हजार 467, गोवा में 1 लाख 42 और लक्षद्वीप में 1,429 मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए। इन सभी मामलों में मृत, स्थायी रूप से शिफ्ट, लापता और डुप्लिकेट वोटर शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है।



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s unchanged.

किसानों की समस्याएँ और फसल बीमा: ज़मीनी संकट और सरकारी दावे – 2025 की तस्वीर

संपादकीय... |

महाराष्ट्र, देश के सबसे बड़े कृषि-प्रधान राज्यों में से एक, इस वर्ष फिर एक बार किसानों की गहरी समस्याओं और फसल बीमा के कार्यान्वयन पर बहस के केंद्र में रहा। 2025 के नवंबर-दिसंबर में राज्य में भारी बारिश, बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण कई जिलों में फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। इन आपदाओं के बीच किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) तथा राज्य की कृषि सहायता योजनाएँ चर्चा का प्रमुख विषय बनीं।

सबसे पहले, सरकारी आंकड़े स्वयं चिंताजनक संकेत देते हैं। राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव ने विधान परिषद में लिखित उत्तर में बताया कि जनवरी से सितंबर 2025 तक राज्य में 781 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें अधिकांश का कारण कर्ज, फसल विफलता तथा अतिवृष्टि रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में संख्या सबसे अधिक रही — नागपुर डिवीजन में 296 और मराठवाड़ा में 212 मामले दर्ज हुए हैं। यह संख्या राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय है, क्योंकि आधे से अधिक किसान आत्महत्याएँ महाराष्ट्र में ही घट रही हैं।

जहाँ एक ओर आत्महत्या के आंकड़े भयावह हैं, वहीं फसल बीमा की वास्तविक कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई PMFBY का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाना है। लेकिन इस योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, उद्योग सूत्र बताते हैं कि अक्टूबर 2025 में अकोला जिले के किसानों को अतिवृष्टि के नुकसान के लिए ₹3, ₹5 और ₹8 जैसा नाममात्र का मुआवजा मिला, जिस पर किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध भी किया।

सरकार ने भी इस योजना को बेहतर बनाने के कई कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रय भारने ने 9 दिसंबर को कहा कि राज्य सरकार और केंद्र ने मिलकर मौसम-आधारित फसल बीमा योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है ताकि रबी 2025-26 के लिए फल, आम और काजू जैसे फलों के उत्पादक भी लाभ उठा सकें।

इन प्रयासों के बावजूद बीमा कंपनियों द्वारा समय पर दावों का भुगतान न होने की शिकायतें जारी हैं। जुलाई 2025 में कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार ने ₹1,015 करोड़ प्रीमियम अभी तक भुगतान नहीं किया, जिस कारण बीमा कंपनियाँ किसान दावों का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि भुगतान जल्द हो जाएगा और पात्र किसानों को राशि 15 दिनों के भीतर मिल सकती है।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीमा कंपनियों को प्रीमियम का भुगतान ही देरी से होता है, तब वास्तविक फसल नुकसान का मुआवजा किसानों तक कब तक पहुँचेगा? किसान आंदोलन और विपक्षी दलों के विरोध ने भी इसी असर को विधानसभा में उजागर किया। राज्य विधानसभा के सत्र में विपक्ष ने सरकार पर किसानों के मुद्दों, विशेषकर कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के सरकारी खरीद केंद्रों पर पर्याप्त खरीद न होने, और MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर विवादित क्रियान्वयन का आरोप लगाया। सरकार ने अपने पक्ष में डेटा पेश किया, लेकिन असंतोष जता कर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

इसके अतिरिक्त, कृषि कार्यों में तकनीकी बदलाव और किसानों की सुविधा के लिए एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लागू किए जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में ई-केवाईसी प्रक्रिया को हटाने और किसानों के लिए पंजीकरण में सरलता लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब पंजीकरण और दावों में देरी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

निष्कर्षतः, महाराष्ट्र में किसानों की समस्याएँ केवल प्राकृतिक आपदा या एकल योजना की विफलता नहीं हैं; यह एक जटिल, बहुआयामी चुनौती है जिसमें आर्थिक असुरक्षा, कर्ज का बोझ, बीमा प्रणालियों की देरी, MSP पर विवाद, और सरकारी नीतियों का प्रभाव शामिल है। फसल बीमा की अवधारणा बुनियादी रूप से सही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन और समयबद्ध भुगतान ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूती दे सकता है।

सरकार और नीति निर्धारकों के लिए असली परीक्षा यह है कि कितनी जल्दी वे किसानों के संघर्ष को नीतिगत प्राथमिकता में बदलकर सतत समाधान प्रदान कर सकते हैं — जिसमें वित्तीय सुरक्षा, बेहतर बाजार व्यवस्था, नई तकनीक और समय पर मुआवजा शामिल हों। तभी महाराष्ट्र के खेतों में वास्तविक अर्थव्यवस्था और किसान जीवन में सुधार की रोशनी दिखाई देगी।

PoK Protests: पीओके में क्यों भड़का विरोध प्रदर्शन, रावलकोट में सड़कों पर अवाम, पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी

● NEWS AGENCY

मुजफ्फराबाद: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन भड़क गया है। रावलकोट में मंगलवार को हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने पीओके में बिजली की अनुचित कटौती, खराब मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के खिलाफ और पत्रकार सोहराब बरकत की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया था।



इस प्रदर्शन के दौरान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी के कोर मेंबर उमर नजीर कश्मीरी ने पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन को कड़ा संदेश दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीओके की सरकार को शाम 5:00 बजे तक का अल्टीमेटम

दिया और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिजली सप्लाई में सुधार की मांग कर

रहे हैं। उनका कहना है कि पीओके में बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाती है, लेकिन इसका लाभ दूसरे सूबों को दिया जा रहा है और यहां के लोग इससे महरूम हैं। लोगों

ने पीओके में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी सुधारने की मांग की। सीमावर्ती इलाका होने के कारण पाकिस्तान ने पीओके में बड़े पैमाने पर इंटरनेट पाबंदियां लगाई हुई हैं। इसके अलावा लोग एक स्थानीय पत्रकार सोहराब बरकत की रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्या चेतावनी दी

घोषणा के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें न मानी गईं तो दो मुख्य रास्ते बंद किए जा सकते हैं। इमें एक ग्रिड स्टेशन की ओर जाने वाला रास्ता है और दूसरा शाहराह-ए-गाज़ी मिल्लत की ओर जाने वाला रास्ता। उन्होंने पीओके के अन्य इलाकों में भी लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।



सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 की नीलामी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये में खरीदा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी लिविंगस्टोन को खरीदने की पूरी कोशिश की, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मार ली।

पहले राउंड में नहीं दिया किसी ने भाव... फिर दूसरी बार में भिड़ गई टीमें, 13 करोड़ में काव्या मारन ने खरीदा ये घातक खिलाड़ी

लियाम लिविंगस्टोन टी20 क्रिकेट में अपने तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि लिविंगस्टोन को नीलामी के पहले राउंड में किसी ने भी नहीं खरीदा था।

पहले आरसीबी में थे लियाम लिविंगस्टोन पिछले सीजन, यानी आईपीएल 2025 में लियाम लिविंगस्टोन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा थे। आरसीबी ने 2025 का खिताब जीता था, लेकिन लिविंगस्टोन का व्यक्तिगत प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 8 पारियों में सिर्फ 112 रन बनाए थे, जिनका स्ट्राइक रेट 133.33 था। उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया था। गेंदबाजी में उन्होंने 9 ओवर डाले

और 8.44 की इकॉनमी से 2 विकेट लिए।

लिविंगस्टोन अच्छी फॉर्म में हैं आईपीएल 2025 के बाद से लियाम लिविंगस्टोन का सफेद गेंद क्रिकेट में प्रदर्शन सुधरा है। उन्होंने 'द हंड्रेड' में बर्मिंघम फीनिक्स की कप्तानी की। वह टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 241 रन 155.48 के स्ट्राइक रेट से बनाए। साथ ही, उन्होंने 7.36 की इकॉनमी से 7 विकेट भी लिए। इसके अलावा, T20 ब्लास्ट में उन्होंने 260 रन 176.87 के स्ट्राइक रेट से बनाए और 6 विकेट लिए। उनकी टीम लंकाशायर सेमीफाइनल तक पहुंची थी। लियाम लिविंगस्टोन एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और दुनिया भर की टी20 लीगों में खेल चुके हैं।

उनकी पावर-हिटिंग की क्षमता उन्हें किसी भी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करके अपनी बल्लेबाजी को और मजबूत किया है।

मजबूत हुई हैदराबाद की बल्लेबाजी आईपीएल 2026 की नीलामी में कई खिलाड़ियों पर बोली लगी। टीमों ने अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को चुना। लियाम लिविंगस्टोन जैसे अनुभवी और मैच-विनिंग खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए बड़ी बात होती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस बार एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश की है।

India Taliban: भारत ने तालिबान से निभाई दोस्ती, अफगानिस्तान को शुरू किया दवाओं का एक्सपोर्ट, पाकिस्तान को बड़ा झटका

काबुल: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब भारत से दवाओं का आयात शुरू कर दिया है। तालिबान सरकार ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की दवाओं की गुणवत्ता खराब है और वे अफगान लोगों पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब काबुल की एक प्राइवेट फर्म के प्रतिनिधियों ने एक जानी-मानी भारतीय कंपनी के ब्रांच ऑफिस के उद्घाटन के साथ भारत से अफगानिस्तान में दवाओं के ऑफिशियली इंपोर्ट शुरू होने की घोषणा की है। 25 तरह की दवाएं मंगा रहा अफगानिस्तान

हुर्रियत रेडियो इंग्लिश के X पोस्ट के अनुसार, शुरुआती दौर में, 25 तरह की दवाएं इंपोर्ट की जाएंगी। इसमें भविष्य में अफगानिस्तान की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रक्रिया को बढ़ाने की योजना है।



दूसरी ओर, अफगानिस्तान फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यूनियन के सदस्यों ने पुष्टि की कि देश में फिलहाल 400 से ज्यादा कंपनियां दवाओं के इंपोर्ट में लगी हुई हैं, जो हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की दवाएं हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अफगानिस्तान को दवा देता रहेगा भारत

रिपोर्ट में बताया गया कि एक भारतीय कंपनी के अधिकारियों ने दवा उत्पादन में अपने 90 सालों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, हेल्थकेयर सेक्टर में अफगानिस्तान के साथ लगातार सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

तालिबान प्रशासित सरकार के पाकिस्तान से दवाओं के इंपोर्ट पर रोक लगाने के बाद, इंपोर्ट करने वालों को दवाएं हासिल करने के लिए दूसरे रास्ते खोजने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद भारत से दवाओं के इंपोर्ट की यह ठोस पहल शुरू हुई।

पाकिस्तान को बड़ा झटका पाकिस्तानी दवा निर्माता कंपनियां हर साल अफगानिस्तान को बड़ी मात्रा में दवाओं का निर्यात कर भारी मुनाफा कमाती थीं। उनकी दवाओं की गुणवत्ता निम्नस्तर की होती थी। इससे पाकिस्तानी कंपनियों की लागत कम आती थी, लेकिन वे अफगानिस्तान को पूरी कीमत पर दवाओं का निर्यात करती थीं। इससे अफगान लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। अब तालिबान सरकार के प्रतिबंध से पाकिस्तानी दवा निर्माता कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार बंद हो गया है। ऐसे में उन्हें दूसरे अल्टरनेटिव को देखना होगा, जहां माल पहुंचाने का लागत अफगानिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा होगा।



संवाददाता चाहिए

नंदिग्राम टाइम्स,
दैनिक समाचार पत्र, नांदेड
को
महाराष्ट्र और नांदेड जिले के
प्रत्येक तालुका और शहर से
संवाददाता की आवश्यकता
है।

यदि आप समर्पित, उत्साही
और अवसर की तलाश में
उभरते या अनुभवी पत्रकार
हैं, तो हमसे तुरंत व्हाट्सएप
पर संपर्क करें।

आपकी कलम ही हमारी
ताकत है!

संपर्क करें

+919921100075

email id-

ntinfodesk@gmail.com

समायोजन में देरी से शिक्षिका का 13 वर्षों का वेतन अटका, शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर

बिलोली / संवाददाता, :

बिलोली नगरपरिषद की प्राथमिक शाला में कार्यरत सहशिक्षिका श्रीमती कादरी अफरोज सुलताना सैयद हसन को शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। समय पर समायोजन न किए जाने के कारण वर्ष 2011 से 2023 तक के पूरे 13 वर्षों का उनका वेतन आज तक लंबित है। सेवा देने के बावजूद वेतन न मिलने से उन्हें लंबे समय तक मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, श्रीमती कादरी वर्ष 2011 से पूर्व लातूर स्थित इस्माईल उर्दू प्राथमिक शाला में कार्यरत थीं। उसी वर्ष उन्हें अतिरिक्त घोषित किया गया लेकिन महाराष्ट्र खासगी शाला



सेवा शर्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के बावजूद उनका तत्काल समायोजन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, वे लगभग 12 वर्षों तक बिना वेतन के उसी शाला में सेवा देती रही। अंततः वर्ष 2023 में उनका समायोजन बिलोली नगरपरिषद प्राथमिक शाला में किया गया, जिसके बाद उन्हें नियमित वेतन मिलना शुरू हुआ।

इस प्रकरण में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि वेतन लंबित रहने का एकमात्र कारण शिक्षा विभाग द्वारा समय पर समायोजन न करना है। आयोग ने शासन से वर्ष 2011 से 2023 तक का संपूर्ण बकाया वेतन तत्काल अदा करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि वर्ष 2019

में माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ ने शिक्षा विभाग की 12 सप्ताह के भीतर समायोजन कर वेतन शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसे न्यायालय की अवहेलना माना जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने भी विधान परिषद में प्रश्न उठाया था।

समायोजन में देरी का असर केवल बकाया वेतन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। अब मांग की जा रही है कि शासन तत्काल हस्तक्षेप कर सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रीमती कादरी अफरोज सुलताना को उनका संपूर्ण बकाया वेतन देकर न्याय सुनिश्चित करे।



हिमायतनगर बस स्टैंड और किसानों के मुद्दों पर विधायक कोहलीकर की सदन में जोरदार 'लक्षवेधी'

नांदेड: नागपुर में चल रहे राज्य विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में हदगांव-हिमायतनगर के विधायक बाबुराव कदम कोहलीकर ने हिमायतनगर बस स्टैंड, किसानों की फसल बीमा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर सदन में लक्षवेधी सूचना प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

विधायक कोहलीकर ने सदन में स्पष्ट किया कि वर्षों से बस स्टैंड न होने से यात्रियों, किसानों और आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि शासकीय कार्यालयों की पुरानी इमारतों का उपयोग कर बस स्टैंड का निर्माण संभव है। इसके अलावा, उन्होंने

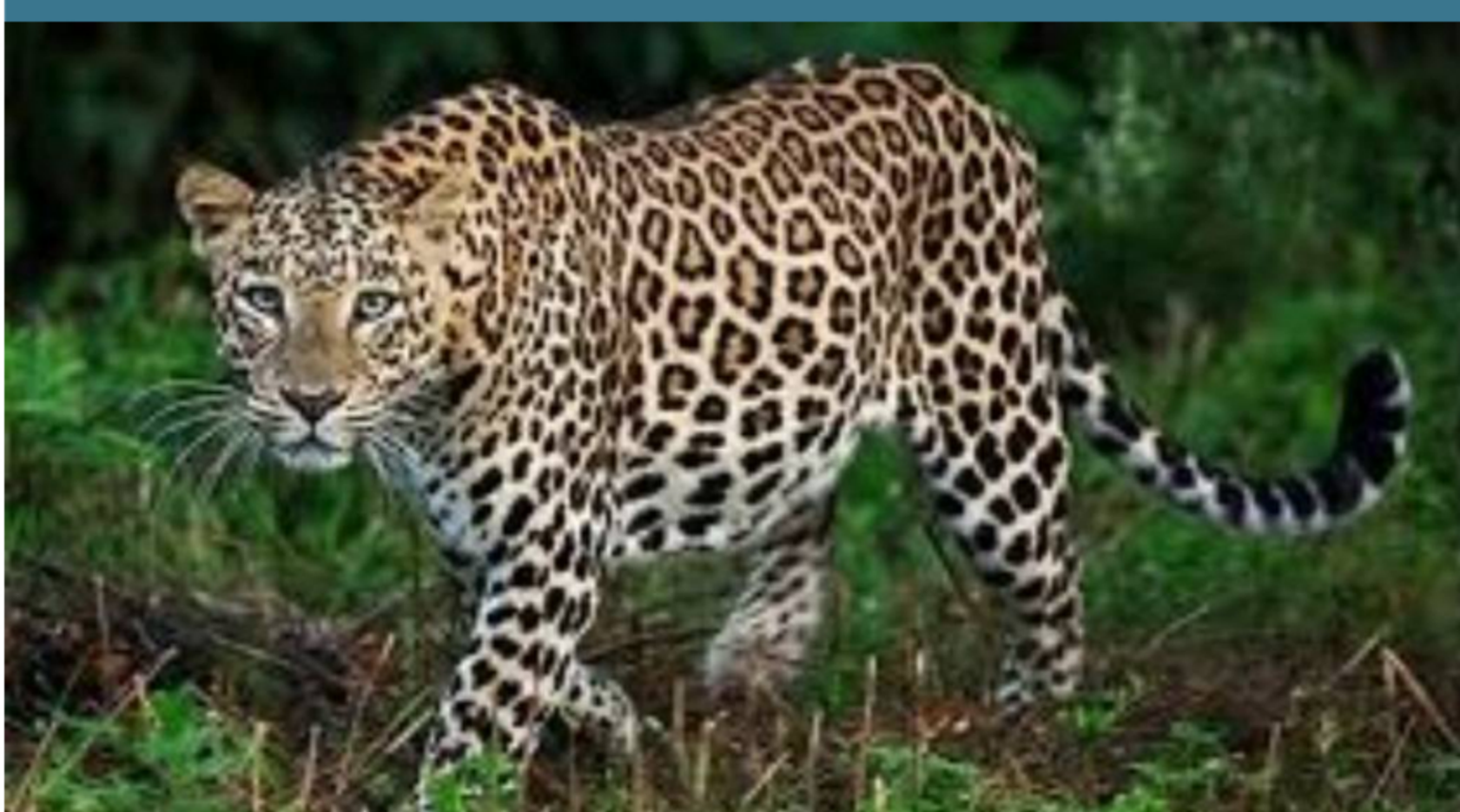
किसानों की फसल बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर भी जोर दिया। लंबी रात तक डटे रहकर कोहलीकर ने क्षेत्रीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से सदन के पटल पर रखा। स्थानीय नागरिकों ने उनके प्रयासों की सराहना की है और शहर के समग्र विकास के लिए निरंतर पाठपुरावे की उम्मीद जताई है।

नांदेड में 25 से अधिक तेंदुओं की दहशत, पिंजरे बेअसर, किसान भय के साए में

नांदेड : नांदेड जिले में तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही ने ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना दिया है। जिले में 25 से अधिक तेंदुओं के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। फसल कटाई के मौजूदा दौर में तेंदुओं के भय से किसान खेतों में जाने से कतरा रहे हैं, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।

वन विभाग को लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर कई संवेदनशील क्षेत्रों में पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अब तक एक भी तेंदुआ इनमें कैद नहीं हो सका है। इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में भोकर क्षेत्र में तेंदुए के हमले में तीन बकरियों को मार दिया गया, जबकि मुखेड तालुका में एक भैंस की

वन विभाग के पिंजरे कब होंगे कारगर?



मौत हो चुकी है। नायगांव तालुका के कृष्णूर परिसर में तेंदुए के हमले में एक किसान गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है और किसानों की उम्मीदें रबी फसल पर टिकी हैं। ऐसे में तेंदुओं की मौजूदगी किसानों की चिंता बढ़ा

रही है। हमलों में लाखों रुपये का पशुधन नष्ट हो रहा है और मानव जीवन भी खतरे में है। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग केवल चेतावनी तक सीमित न रहे, बल्कि तेंदुओं को पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

नांदेड महापालिका की 81 सीटों पर चुनावी रणधुमाल, तीन साल बाद बजा चुनावी बिगुल

नांदेड | तीन वर्षों से प्रशासक राज झेल रही नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका के चुनावों का आखिरकार बिगुल बज गया है। सोमवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही शहर की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। 20 प्रभागों की कुल 81 सीटों के लिए अब सीधी मुकाबले की स्थिति बन गई है। सत्ता हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 23 से 30 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 31 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 2 फरवरी तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। 3 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन और अंतिम उम्मीदवार सूची जारी की जाएगी। 15 फरवरी को मतदान होगा और 16 फरवरी



को मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका की अवधि 31 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद से यहां प्रशासक राज चल रहा था। करीब तीन साल के लंबे इंतजार के बाद अब नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना को देखते हुए हाल के दिनों में सत्ताधारी दल की ओर से विकास कार्यों के भूमिपूजन

का सिलसिला भी तेज देखा गया। चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया था। निजी क्लासेस और कॉलेजों के पते पर हजारों मतदाताओं के नाम दर्ज होने, साथ ही अन्य राज्यों के श्रमिकों को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाने के आरोप लगे थे। इन आपत्तियों के बाद सुधार की प्रक्रिया चल रही है और 20 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। राजनीतिक समीकरणों की बात करें

तो हाल ही में हुए नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दल अलग-अलग लड़े थे। प्रचार के दौरान महायुति के घटक दलों में तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। वहीं कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच भी ऐन वक्त पर दूरी बढ़ गई थी। ऐसे में महापालिका चुनाव में गठबंधन किस रूप में सामने आते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

इस बार चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन पत्र ऑफलाइन जमा करने की अनुमति दी है। पिछले चुनावों में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के कारण उम्मीदवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऑफलाइन व्यवस्था से अब उम्मीदवारों को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करने का अवसर मिलेगा, जिससे चुनावी माहौल और अधिक गरमाने की संभावना है।

कुल मिलाकर, नांदेड महापालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ चुका है और आने वाले दिनों में शहर में चुनावी रणधुमाल और तेज होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं।



हिमायतनगर: करोड़ों का अस्पताल, स्टाफ नदारद-मरीज बेहाल, जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप की मांग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद मरीज उपचार की आस लेकर इस अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन यहां स्थायी चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। एक्स-रे, ईसीजी और सोनोग्राफी जैसी जरूरी जांचों के लिए मरीजों को "सुविधा उपलब्ध नहीं है" कहकर वापस भेज दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि डिजिटल एक्स-रे, सोनोग्राफी और ईसीजी की मशीनें अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन स्टाफ और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये मशीनें चालू ही नहीं की गईं। डिजिटल एक्स-रे मशीन अब तक पैक हालत में पड़ी बताई जा रही है, वहीं ईसीजी मशीन ऑपरेटर समय पर उपलब्ध नहीं रहता।

अस्पताल में सुबह ओपीडी से लेकर शाम तक

कुल 12 नर्सिंग स्टाफ स्वीकृत होने के बावजूद केवल 4 नर्सों के भरोसे पूरे अस्पताल का काम चलाया जा रहा है। उपजिला अस्पताल का दर्जा मिलने के बाद भी न तो मेडिकल स्टाफ बढ़ाया गया और न ही सेवाओं का विस्तार किया गया, जिसके चलते मरीजों को केवल दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

इधर, लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से बनी नई अस्पताल इमारत का निर्माण कार्य दो वर्ष पहले पूरा होने के बावजूद अब तक उसे अस्पताल प्रशासन के सुपुर्द नहीं किया गया है। आरोप है कि निर्माण कार्य घटिया दर्जे का हुआ है। लिफ्ट होने के बावजूद उसे स्थापित नहीं किया गया, वहीं बारिश के दौरान इमारत से पानी टपकने की शिकायतें सामने आई हैं। जबकि

पुराने भवन में जगह की भारी कमी है, फिर भी नई इमारत का उपयोग न होना कई सवाल खड़े करता है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। मरीजों और नागरिकों में गहरा रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जिला स्वास्थ्य प्रशासन और जनप्रतिनिधि तत्काल हस्तक्षेप कर स्टाफ की नियुक्ति, जांच सुविधाओं को शुरू कराने और नई इमारत को जल्द अस्पताल के उपयोग में लाने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की परेशानी दूर हो सके।

● ● ● ● ● ●